BJS

Bharatiya Jain Sanghathan

Benefits of Minority for NGO

2014

Compiled from Internet and Published by :

Shri. Shantilal Muttha *for* Bharatiya Jain Sanghathan (BJS)
Muttha Towers, Don Bosco Road, Near Golf Course,
Yerawada, Pune - 411 006. India.
Tel.: 020 - 4120 0600
Email: info@bjsindia.org
Website: www.bjsindia.org

Printed at:
Prabhat Printing Works,
427, Gultekdi, Pune 411 037. India.

For Private Circulation only.

Price :₹ 25/-

(Set of 6 Books ₹ 200)

Edition : March 2014

INDEX

Sr. No.	Name	Page No.
Chapter 1	Preface	1
Chapter 2	Constitutional Provisions	5
Chapter 3	Scheme Of Grant-in-Aid By Maulana Azad Education Foundation	7
	Chapter 3a-Application Form For Financial Assistance Of Maulana Azad Education Foundation	16
Chapter 4	Scheme Of Micro Financing By NMDFC	24
	Chapter 4a-Application Form for Availing Interest Free Loan	29
Chapter 5	Addresses	37
	Chapter 5a-Addresses Of National Commission For Minorities	37
	Chapter 5b-Addresses Of State Minorities Commission	38
	Chapter 5c-Addresses Of State Channelising Agencies Of NMDFC	41
Chapter 6	Gazette of India For Jain Minority	46
Chapter 7	About Bharatiya Jain Sanghathan (BJS)	47

Chapter 1

Preface

२७ जनवरी २०१४ को भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार एवं सक्षमीकरण के कई विशेष प्रावधान है। इसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग एवं अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। जनवरी २०१४ तक मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चयन, सिख एवं पारसी धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। अब जैन धर्म को भी यह अधिकार प्राप्त है।

जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए या नही इस पर मतभिन्नता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि, जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने से जैन समाज मुख्य प्रवाह से दूर हो जायेगा। कुछ लोगों को लगता है कि, इस घोषणा से जैन समाज को आरक्षण का दर्जा मिलेगा जो कि निम्न जाति के लाभ के लिए है। यह मतभिन्नता संपूर्ण जानकारी के अभाव की वजह से है। अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने की वजह से, जैन समाज इस देश के मुख्य प्रवाह से दूर हो जायेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ना ही अल्पसंख्यक याने आरक्षण है। इसके विपरित अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से जैन समाज के सभी धर्मस्थल, धार्मिक संस्थाएँ, संस्कृती, भाषा व लिपी सुरक्षित रहेगी। जैन समाज अपनी रूचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगा और उसका प्रशासन भी कर सकेगा। जैन समाज आर्थिक दृष्टी से सुसंपन्न समाज है, ऐसी धारणा है, यह अंशत: सत्य भी है। तथापि इस समाज में बहुत बडा मध्यम वर्ग है व अल्प आय प्राप्त करने वाला वर्ग भी है। जिन्हें दैनंदिन जीवन जीने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की अनेक योजनाओं के लिए प्रति वर्ष करोडों रूपये का प्रावधान बजट में किया जाता है। अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की वजह से अब जैन समाज को भी इन सारी योजनोओं में

हिस्सा लेने का एवं विविध योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त होगा । यह जैन समाज के उत्थान के लिए बडी बात है।

देश में आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इन राज्यों में जैन समाज को पहले से ही राज्यस्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। इन सभी राज्यों में राज्यस्तर के अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ उन उन राज्यों के जैन समाज के लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की योजनाओं में काफी भिन्नता है। अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए राज्य स्तर की योजनाओं से काफी ज्यादा योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। जैन समाज के विद्यार्थियों कि शिक्षा एवं छात्रवृत्ति कि विविध योजनाएँ, शैक्षणिक संस्थाओ कि स्थापना एवं प्रशासन की विविध योजनाएँ, युवतियाँ एवं महिलाओं के सक्षमीकरण की योजनाएँ, व्यवसाय के विकास की विभिन्न योजनाएँ, धर्मस्थान की सुरक्षा की विभिन्न योजनाएँ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज उत्थान की विविध योजनाएँ उपलब्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने की वजह से इन सभी योजनाओं की जानकारी जैन समाज के घर घर तक पहुँचाना आवश्यक है।

भारतीय जैन संघठन सन १९८५ से देशभर में सामाजिक उत्थान एवं शैक्षणिक विकास का कार्य कर रहा है। देश में जैन समाज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा २५०० शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण सौं डेढ़सौं वर्ष पूर्व किया गया। इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, सभी जाति-धर्म के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा, सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। भारतीय जैन संघठन द्वारा सन २००२ में फेडरेशन ऑफ जैन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट की स्थापना की गई। जैन समाज की १७०० शैक्षणिक संस्थाएँ इस फेडरेशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने की वजह से इन शैक्षणिक संस्थाओं को विकास के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक कानून, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री १५ सूत्री कार्यक्रम एवं संबंधित अन्य विभाग तथा

वेबसाईट का अध्ययन कर, भारतीय जैन संघठन द्वारा ६ पुस्तकों का संकलन किया गया है। आशा है कि, निम्नलिखित पुस्तकों के माध्यम से अल्पसंख्यक योजनाओं व लाभ की जानकारी जैन समाज के सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन विद्यार्थियों को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की धार्मिक संस्थाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन महिलाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन व्यवसायियों को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन सामाजिक संस्थाओं को लाभ

आप यह पुस्तके भारतीय जैन संघठन के मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते है अथवा www.bjsindia.org वेबसाइट से भी डाऊनलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करे।

भारतीय जैन संघठन,

मुथ्था टॉवर्स, डॉन बॉस्को मार्ग, गोल्फ कोर्स के पास, येरवडा, पुणे - ४११ ००६.

आपसे विनम्र निवेदन है कि, उपरोक्त जानकारी जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करे।

धन्यवाद,

शांतीलाल मुथ्था

संस्थापक

Chapter 2

Constitutional Provisions

The Basis for Benefits to Minorities: The Provisions made in the Constitution of India.

The all encompassing Constitution of India has made provisions through some Articles that allow for granting of additional benefits to minority communities. The Articles of the Constitution of India under which benefits provided to educational Institutes having a Minority certification are :

The Articles 29 and 30 of the Indian Constitution cover cultural and education rights. Articles 347, 350 and 350A relate to usage of a language as medium of instruction, for communication and for representation to redress of grievances.

Art 29. Protection of interests of minorities:

(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Art 30. Right of minorities to establish and administer educational institutions:

(1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such

law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.

(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Art.347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State:

On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognized by that State, direct that such language shall also be officially recognized throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Art 350. Language to be used in representations for redress of grievances:

Every person shall be entitled to submit a representation for the redressal of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Art. 350A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage:

It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Chapter 3

Scheme Of Grant-in-Aid By Maulana Azad Education Foundation

Introduction:

The Foundation was established on the occasion of Maulana Abul Kalam Azad's birth centenary celebrations. His eventful life was packed with outstanding achievements in the diverse fields. He was towering figure on the Indian political scene and a scholar rated high in the realms of Urdu Literature. To this, he added a trend-setting innings as a journalist. But his greatest claim to fame was his contribution as a thinker with a world vision and humanist outlook. A dogged freedom fighter and an un-failing upholder of secular and democratic values. Maulana Azad deserves to be introduced afresh to the modern generation of Indians.

The Foundation is a voluntary, non-political, non-profit making social service organization, established to promote education amongst educationally backward sections of the Society. It is funded by the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India. The Hon'ble Minister of Minority Affairs is Ex-Officio President of the Foundation. It was registered under the Societies Registration Act, 1860 on 6th July 1989.

The details about the schemes of providing financial assistance to NGOs being undertaken by the Foundation and the prescribed formats of application are given in the following pages.

Objective Of The Scheme:-

To provide basic educational infrastructure and facilities in the areas of concentration of educationally backward minorities which do not have adequate provision for elementary, secondary and Sr. Sec. Schools / Jr. Colleges / Professional & Vocational Training Institutes.

Purpose Of Which Grant-In-Aid Is Provided:-

Financial assistance for construction/ expansion of Schools belonging to educationally backward minorities, Financial

assistance for purchase of Science/Computer lab equipments/furniture for institutions belonging to educationally backward minorities, Financial assistance for purchase of equiments / construction/ Expansion of Vocational Training Centre/ ITI/Polytechnic belonging to educationally backward minorities, Financial assistance for construction of Hostel building in the institutions belonging to educationally backward minorities, Financial assistance for construction/Expansion of D.Ed / B.Ed. College belonging to educationally backward minorities,

Eligibility Criteria For Grant :

Society/Trust should be registered under the Societies Registration Act/ Indian Trust Act for the last three years, The NGO must be having properly constituted Managing Committee with its powers clearly defined in its by-laws, Society/Trust must be having proper audit reports with Balance Sheet, Receipt-Payment & Income-Expenditure statements reflecting educational activities carried out for the last three years, Society/Trust should be in a position to receive involvement of knowledge-able persons for furtherance of their programmes on voluntary basis, Society/Trust should not be run for the profit of any individual or a body of individuals/ family and it should not be controlled by any individual or a body of individuals / family. The members from one family should not be more than 30% in the Managing Committee. The NGO will have to attach an affidavit on Rs. 20/- stamp paper that the members belonging to one family are less than 30%.

The institutions for whose construction/expansion the assistance is required should be in existence and recognized/affiliated to the concerned State/Central Board/ Council/ University, Society/Trust should not be functioning for furtherance of the interest of any political party, Society/Trust should not in any manner incite communal disharmony, The majority (ie, more than 50%) of the beneficiary students, in the Institution for whose construction expansion/ strengthen assistance is sought, should be belonging to educationally backward minorities/target group, For seeking assistance for construction of hostel building, it is necessary that the Institution for which the hostel is required should be recognized at least up to 8th standard, Society/Trust must be having at least 500 sq. yard land (in urban areas) or at least half acre land (in rural areas) in its name or on lease for not less than 30 years for the

proposed project, Society/Trust should be ready to invest at least 10% of the total cost of project as NGO's share on the project.

The Society/Trust will not take loan on the building constructed with MAEF assistance/ on the land on which the building has been constructed with the assistance of the Foundation. However, if it becomes necessary, then prior permission of the Foundation for the same will be necessary.

The Institution recognized by Madarsa Boards or running as study/examination centers of NCPUL, NIOS, MANNU, etc. are not entitled for getting grant from MAEF.

Guidelines for submission of Proposal:

The Society/Trust seeking assistance under the Scheme shall apply for purposes specified on the prescribed proforma given at Annexure -I to VII, Backward areas, particularly areas that are educationally backward should receive appropriate attention/priority, Assistance to an individual unit should not exceed Rs.30.00 lakhs. and propsal for only one purpose will be accepted at a time. For details and ceiling limit see Annexure -A, The grantee should undertake to name the entire beneficiary institution or a part of it after Maulana Abul Kalam Azad, The Scheme may be revised as and when required and no claim will be entertained from any Organization/Institution for consideration as a permanent beneficiary, The applications may be sent to the Foundation by post or may be submitted personally in the Foundation office on all working days between 10.00 A.M to 5.00 P.M. from May 1st to 30th September every year. The incomplete proposals will not be accepted, and the same will be returned back pointing out the deficiency. Revised complete applications resubmitted will be treated as fresh applications, The Checklist available at Annexure -I should be filled carefully and the page numbers of each document should be mentioned properly. No column should be left blank. Each page must be signed, Only one proposal will be entertained at a time., Each document/enclosure attached to the application, must be certified/attested by Society/Trust official or Notary Public.

In case of application for Girls/Boys Hostel building, a note justifying the need of Hostel building in the Institution shall be submitted separately. However while considering the proposals for

construction of Hostel buildings, preference will be given to the Institutions, which are already running hostels.

Procedure for sanctioning financial Assistance under the scheme:

On receipt of proposal, it will be scrutinized in the office of the Foundation, and the shortcomings will be communicated to the Organization/ Institution by registered post.

The complete proposals shall be referred for inspection, which shall be carried out through State Government officials, members of the Foundation or by any other person to whom the Foundation may entrust this job, The inspection reports shall be placed before the Sub-Committee/ Governing Body of the Foundation for consideration and the decision shall be communicated to the Organization / Institution.

Ceiling Limits For Sanction of Grant-In-Aid Under Various Categories

No.	Category	Ceiling limits (Rs)
1.	If the School is recognized up to 5th standard, running in rented building & own building required.	10,00,000
2.	If the School is recognized up to 5th standard & to be upgraded up to 8th standard	06,00,000
3.	If the School is recognized up to 8th, running in rented building & own building required	15,00,000/-
4.	If the school is recognized up to 8th standard & to be upgrade up to 10th standard	08,00,000/-
5.	If the School is recognized up to 10th running in rented building & own building is required	20,00,000/-
6.	If the School is recognized up to 10th standard and to be upgraded up to 12th standard	10,00,000
7.	If the school is running up to 12th standard, running in rented & own building is required	25,00,000
8.	If the school is running up to 12th standard and expansion of building is required	15,00,000
9.	Purchase of lab equipments in Schools recognized up to 10th Class (physics/chemistry/biology/computers)	03,00,000

10.	Purchase of lab equipments in Schools recognized up to 12th class (physics/chemistry/biology/computers)	05,00,000
11.	Purchase of furniture/computers for schools recognized up to 8th class/5th class	02,00,000
12.	For construction of Hostel buildings	
	a) 100 bedded dormitory type hostel building	30,00,000
	b) 50 bedded dormitory type hostel building	15,00,000
	c) 30 bedded dormitory type hostel building	10,00,000
13.	i) For expansion of D.Ed. College bldg.	10,00,000
	ii) For expansion of B.Ed. College bldg	15,00,000
14.	i) For construction/ expansion of Vocational Training Centre (VTC) bldg	15,00,000
	ii) For purchase of equipments/tools/machines for VTC	05,00,000
15.	i) For construction/ expansion of Technical Institute/ ITI/ITC bldg	10,00,000
	ii) For purchase of equipments/machines/tools for Technical Institute/ITI/ITC	08,00,000

note : a) 100 bedded Hostel may be provided only if the Institution is already having hostel facility with at least 50 bedded accommodation. Initially 30 bedded hostel may be provided on experimental basis.

b) For girl's school from class 8th onwards bathroom must be the part of the building.

c) The existing rate of construction as per CPWD is Rs. 800/- per sq. ft. but the same varies in different states according to the situation of the area.

Check list of documents required to be attached With the application

(To be filled by the Applicant)

Sr. No.	Documents	Page no.
1	Duly filled application form, i.e. Annexure - I to VII	
2	Certified copy of Registration Certificate	
3	Certified copy of Memorandum of Association & Rules-Regulations or Trust Deed	
4	Certified copy of the present list of members of the NGO as per Annexure -III The members from one family should not be more than 30% in the managing committee. The NGO will have to attach an affidavit on Rs. 20/- stamp paper committee. The NGO will have to attach an affidavit on Rs. 20/- stamp paper that the member belonging to one family are less than 30%.	
5	Annual Report/Brief History of the activities of the NGO for last three years	
6	Certified copy of Audit Report with Balance Sheet, Receipt/Payment & Income/ Expenditure statements of the NGO for the last three years	
7	Certified copy of permission/recognition/affiliation certificate of the School/ College/Institute	

8	Certified copy of land/building title deed, i.e. registered Sale Deed/Gift-Deed/ Exchange- Deed or Allotment Order or Lease-Deed (for not less than 30 years) in the name of NGO or Certified copy of the revenue record of land proposed for construction clearly reflecting name of the Institution/Organization	
9	Search Report or Title Certificate with brief history of land proposed for construction or available building from an Advocate	
10	Certified copy of the Certificate for change in use of land, i.e. from Agricultural to Non-Agricultural from the competent authority (if the proposal is for civil construction & the land is agricultural)	
11	Certified copy of approved site-plan for the proposed construction, (if the proposal is for civil construction)	
12	Detailed Estimate item wise for the proposed construction prepared by Chartered Architect/Licensed Engineer, (if the proposal is for civil construction)	
13	Quotations from at least three standard firms for the equipments/computers/furniture to be purchased with comparative statement (if the proposal is for purchase of equipments)	
14	Details of Trades being run & proposed trades with syllabus (if the proposal is for ITI/Polytechnic/VTC	
15	Three post card site photographs, from different angles of the existing School/ College/Institute building	

16	An affidavit on Rs 20/- Stamp paper that the institution, for which Grant-in-Aid is sought, is being run and managed by the applicant Society/Trust.	

Note: 1) Please send duly filled prescribed proforma along with all essential documents. If the application is found incomplete & the deficiencies are not removed before last date, i.e. by 30th September, the file will be closed and no further correspondence will be entertained,

2) If the proposal is for purchase of lab equipments / computers / furniture / tools & machinery for School / College /VTC / ITI then documents mentioned at S. No. 10, 11, & 12 in the Checklist will not be required.

3) If any of the documents are in the regional language then their notarized English / Hindi version is compulsory.

Chapter 3a

Application Form For Financial Assistance Of Maulana Azad Education Foundation

(Please tick (√) the purpose in the appropriate box)

- Construction/Expansion of School building
- Construction/Expansion of D. Ed/B. Ed. College building
- Construction of Girls Hostel building
- Construction of Boys Hostel building Purchase of Science / Computer lab equipments/furniture for school
- Construction/Expansion of Vocational Training Centre / ITI / Polytechnic Purchase of equipments/machinery/ tools/furniture for VTC/ITI Polytechnic

1	Name & full address of the Society/Trust with pin-code/phone/fax number	:
2	Name & address of the Institution for which assistance is required with pin-ode/phone/fax number	:
3	Contact person (with name, designation, address and phone number)	:
4	Status of application (Society/Trust)	:
5	Nearest Railway Station with distance in K.M.	:
6	NGO's registration number, date & place of registration (attach certified copies of Registration Certificate, Memorandum of Association & Rules Regulations/Trust Deed & List of Members, as per Annexure -III)	:
7	Brief background/educational activities & other	:
8	(a) Financial assistance required (both in words & figures)	:
	(b) Purpose of financial assistance	:
9	How much amount NGO would be investing from its own resources on the proposed project	:

10	**Financial assistance if any received from Govt., Local Body, other organization (indicate the amount received with purpose on each account during last three years)**	:
11	Financial assistance, if any received from Maulana Azad Education Foundation/Central Wakf Council earlier, if yes, enclose copy of Utilization Certificate	:
12	Funds in the Bank A/c of NGO (attach certified copies of Audit Reports with Balance Sheets,Receipt/Payment & Income / Expenditure statements of the NGO)	:
13	Who are the intended beneficiaries	:
14	Number of minority institutions in the area	:
15	Whether the Institution is running in its own or rented building (attach three post card size photo of existing building	:
16	Level of Institution (by Recognized or Unrecognized) attach certified copy of recognition/ affiliation certificate, copy of Board result-sheets, or details of result as per Annexure-V, details of students as per Annexure -VI & details of teachers as per Annexure -VII	:
17	Class-wise/Trade-wise fees charged by the Institution (attach details as per Annexure -IV)	:
18	Detail of accommodation available	:
19	Area of land/total building available (mention in sq. yards/acres) (attach papers as per checklist)	:
20	Proper justification for construction of Hostel Boys/girls building (use separate sheet)	:

21 **Details of existing trades (if proposal is for VTC/ITI/Polytechnic)** :

22 Details of new trades (if proposal is for VTC/ITI/Polytechnic) :

I hereby declare that the information given in this application are true & correct to the best of my knowledge & belief.

Dated:----------

Place:----------

Signature with full name &

Seal of the authorized person of the NGO

General instructions:

Please fill in all columns,

- Please attach documents as per checklist carefully with proper numbering on each page,
- If the required documents are in regional language, then certified English/Hindi version of the same shall also be attached,
- Each page of application document attached must be signed/stamped by the President/ secretary of the Society/Trust. List of Members

Sr. No.	Name of Member	S/O or D/O	Full Address with Telephone Number	Designation
Seal & signature of the Principal of Institution			Seal & Signature of the President/Secretary/Manager of the Society/Trust	

Fee Structure (Class wise/ Trade wise)

Sr. No.	Class / Trade	Fees Charged Monthly	Fees Charged Yearly	If Any Concession Are Given

Seal & signature of the Principal of Institution	Seal & Signature of the President/Secretary/Manager of the Society/Trust

Details of Board Exam Results

Year	Class	Total Number Of Students Appeared	1st Div	2nd Div	3rd Div	Pass	Fail	% Age

Seal & signature of the Principal of Institution	Seal & Signature of the President/Secretary/Manager of the Society/Trust

Details Of Students Required To Be Attached With Annual Report

Academic Year :

Sr. No.	Class	Students Belonging To Minorities					Students Belonging To Other Communities			Grand Total
		Muslims		Others		Total	Boys	Girls	Total	
		Boys	Girl	Boys	Girl					

Seal & signature of the Principal of Institution

Seal & Signature of the President/Secretary/Manager of the Society/Trust

Details of Teachers

Sr. No.	Name of the teacher	Qualification	Work experience	trained/ Untrained

Seal & signature of the Principal of Institution	Seal & Signature of the President/Secretary/Manager of the Society/Trust

Chapter 4

Scheme Of Micro Financing By NMDFC

Scheme Details

NMDFC took the lead to start a parallel channel of micro financing w.e.f. 1/4/1998. This initiative was taken in order to reach the poorest among the target group, especially the minority women scattered in remote villages and urban slums who are not able to take advantage of the formal banking credit as well as NMDFC programme through its SCA. Under this scheme small loans up to a maximum of Rs. 25,000 per beneficiary are provided through the network of NGOs and SHGs. Funds are given to the NGOs at an interest rate of 1%, which further do the lending to the beneficiaries directly or through the SHGs at an interest rate of 5%.

Scheme Guidelines

The eligibility conditions for the Minority members, Self Help groups, NGOs, loan amount, interest rate etc. would be as per the scheme of Micro financing of NMDFC.

1. Introduction

As per the scheme of micro-financing of NMDFC, an interest free loan of Rs.2.15 lacs is available to each selected NGO for the purpose of promotion of self-help groups. Self-help groups are extremely helpful in allowing NGOs to know a large number of individuals intimately and relate to them in a variety of ways including facilitating credit availability. Self-help groups become more important for expanding the activity of the NGOs in new and virgin areas. They serve as decentralised centres of administration for NGOs. Such groups become significant agents for bringing about changes in the lives of members.

2. Definition Of Self-Help Groups

A homogeneous group will be of 15- 20 eligible beneficiaries each. These persons may select their own leader and also fix the tenure for such leadership.

3. Specific Functions To Be Performed By SHGs

I. Emphasising that there is a great strength in getting united.

II. Effecting regular saving and credit activity within the group, which would follow explanatory sessions on the difference between consumer credit, production credit and the use of credit for socio-economic transformation in the lives of the members of the SHG.

III. Analysis of the existing formal and non-formal credit system.

IV. Articulation of the groups' requirement in terms of credit, enhancement of skills required for Income Generation activity.

V. Facilitating easy access to credit and instituting the mechanism for its effective channelisation.

VI. Teaching importance of regular repayment and using group dynamics for the same.

VII. Applying viable norms for interest rates, repayment schedules, gestation period, extension, writing off bad debts and the requirements for communication with the financing institution.

VIII. Serving as platform for review of the cost benefit of the income generation activities being undertaken.

IX. Undertaking identification of needs for up-gradation of technical skills in the IG activity undertaken.

X. Any other activity including consideration of social issues impinging on the lives of the beneficiaries.

4. Important Steps For Promotion Of SHGs

a) The most important step for formation of SHGs is to conduct a socio-economic survey of the village. The survey report would enable the NGO to identify the needy economic groups in the village and the crafts/business, they want to follow.

b) Conducting the first meeting in the village.

c) Identification of the other problems of the women, including social and medical problems, if any.

d) Building a consensus for working together, defining groups dynamics and rules which will develop the group on a sound basis.

e) Discussions and determination of the programmes that will be undertaken by the members of their group.

f) Identification of an effective and appropriate group leader for conducting group activities.

g) Steps for ensuring effective working of group by participation in open, friendly and congenial atmosphere, giving respect to the view of all members and to ensure that the group stand by itself.

5. Estimated Expenditure On Formation Of SHGs

i) There are different patterns followed by NGOs about incurring expenditure on formation and stabilisation of groups. However, it can generally be said that expenditure is required on the following important heads:

a) Surveys and village-wise promotional meetings;

b) Training of leaders and members;

c) Exposure visits for leaders and members;

d) Monitoring of the regular meetings and other activities of the group;

e) Meeting of groups' representative and annual meetings;

f) One full-time facilitator (for at least 10 to 12 groups) to give guidance and lead;

g) Animator's honorarium;

h) Miscellaneous (records, books etc.)

ii) Experience and discussion in the field indicate the minimum broad expenditure required to be incurred on a unit of 50 groups in about 25 villages in accordance with the scale as follows:

(Rs. per year for 50 Groups)	Amount in Rs.
a) Survey and village promotional meeting (per village: Rs.1,000/-)	25,000.00
b) Training of leaders and members in saving, credit and developmental activities & skills up-gradation and exposure visits for the leaders/ members (Rs.1,000/- per group)	50,000.00
c) Supervision of monthly meetings & meetings of group representatives (4 in a year) - One Facilitator & 4 Extension workers salary etc. (5xRs.18,000/-)	90,000.00
d) Annual meet of all members once in a year (Rs.200/- per group)	10,000.00
e) Leaders' honorarium and travel (Rs.600/- per group)	30,000.00
f) Misc. (Records, books and other contingencies) (Rs.200/- per group)	10,000.00
TOTAL	2,15,000.00

iii) The total thus comes to about Rs.2,15,000/- for about 1,000 members i.e. an expenditure of about RS.215/- per member. Initially 50% of the sanctioned amount will be released and after observing the progress the remaining would be released.

6. Eligibility Criteria For Getting Assistance For Group Formation

NGOs which will be eligible to get assistance should have been at least 3 years old and registered ones. Such NGOs should either be the borrower of NMDFC or for becoming borrower of the NMDFC immediately or in the course of another one or two years. The NGO would be required to comply with the following other conditions:

a) It has a good record of performance in various developmental activities, particularly in promoting economic activities for women;

b) It should not be in deficit as reflected through its income and expenditure statement as well as balance sheet;

c) It has necessary infrastructure for promotion of Self-Help Groups;

d) It has no resources or financial assistance for the purpose of promotion of the new groups from any other source;

e) Should have been implementing socio economic developmental programmes in the past 3 to 4 years.

7. Disbursement Of Assistance

The NGO will apply in the prescribed format.

Assistance would be provided in the form of interest free loan to the NGO (in one or more installments). Each loan will be repayable after one year repayment holiday (so as to provide time for operational/stabilisation of the SHG) by giving grants to the NGO every year (from 2nd year onward) on the following scale:

a) 25% of the loan amount advanced by the SHGs promoted under the NMDFC's micro financing scheme.

b) 5% on the growth of savings (provided the growth in savings is at least 10% over the last year)

This will be adjusted maximum in three years.

Chapter 4a

Application Form for Availing Interest Free Loan

For The Purpose of Promotion and Development of Self Help Groups (SHGs)

1. Organisation Directory

a) Name of the Organisation : _____

b) Address : _____

c) State : _____

d) District : _____

e) Block : _____

f) Phone No. : _____

(With STD Code)

g) Fax No .(if any) : _____

h) Nearest Railway Station : _____

i) Registration NO. of the : _____

Organisation

j) Date of Registration : _____

k) Date of Renewal, if any : _____

L) Area of Operation

I) As per Memorandum of Association : _____

(MOA)

ll) For implementation of this programme : _____

m) Name and branch of the Bank from where the NGO operates: : _____

n) Account No. : _____

o) Name and Designation of Chief Functionary : _____

2. Main Objectives of the Organisation

3. Whether the NGO is already collaborating with NMDFC

YES/No (Please Tick)

4. If yes, collaborating since when and under which scheme

Year	Name of the Scheme

5. Description of socio-economic development programmes implemented by the organisation during the last years (year wise)

Sr No	Year	Name of The Programme	Name of the Agency	Programme Sanctioned			Achievements			Other Remarks
1	2	3	4	5			6			7
				Date of sanction	Physical Units	Financial Assistance	Date of Sanction	Physical Units	Financial Assistance	
				5A	5B	5C	6A	6B	6C	

Note : Please enclose a copy of your annual reports of last three years.

6. Experience of the Organisation in thrift/savings and formation of SHGs.

Please give details as below (position as on _____)

S. No.	Name of SHG	Name & address of the leader SHG	Name of Village	No. of total Member *(No. & classification accordingly)		Period since when formed i.e. Date of formation	Whether bank a/c has opened and number alongwith name of bank /branch	Saving per member per month (Rs.)	Total saving collected by the group (Rs.)	Total credit to the group members from its own savings (Rs.)	Total amount due to be recovered till date (Rs.) i.e.. demand	Total amount recovered (Rs.) i.e. repayment	% of recovery column (13/12)x100	Amount of loan Outstanding (Rs.)
				No	Class									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note : * No. of total member of every SHG is to be classified into the categories as mentioned below :-

M- Minority, S - SC & ST, D - Disabled and OBC - Other Backward Class.

7. Experience of the organisation in credit activity during last 3 years (year wise) (Amount in RS.)

Sr. No	Years	Name of Activities for which loans given	No. of SHGs	No. of Borrowers	Amount of loan disbursed	Amount Which was due for recovery i.e. Demand	Amount actually recovered i.e. repayment	%age of Recovery to Demand column (8/7)x100	Source of funds
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. a) Details of infrastructure & manpower available for implementing NMDFC programme.
   b) Infrastructure Building: Own/ rented (Please tick) Training Hall/ Auditorium etc. (details to be given)
   c) Details of training programme conducted if any, by the organization during the last one year.
   d) No. of extension staff available with NGO for promoting groups.

Sr. No.	No. of staff working with the organization	Trained		Untrained	Total
1	2	3		4	5
		No. of Persons	Years of Experience in Micro Credit i.e. in SHG formation		
		3A	3B		
	Headquarters: a) Accounts/ office staff				
	b) Supervisory staff				
	c) Extension staff				
	Total				

9. Financial sources available to NGO from itself or from donors for the purpose of promotion & development of SHGs.

Sr. No.	Source	Balance of the beginning of year	Amount expected during the current year	Total Amount
1	2	3	4	5
1.	Own sources			
2.	Other sources such as Borrowing etc. (Please indicate the name of the agency)			

10. Details of SHGs programme to be taken up under NMDFC scheme (only realistic programme to be given).

Sr. No.	Year	No. of SHGs to be promoted		Expected No. of Members		Estimated	
		Name of the Village*	No. of the SHGs**			Amt. of savings to be generated	Amt. of lending to be made
1	2	3	4	5		6	7
				I year II year III year			
				Total			

* Attach the list of villages where SHGs are to be promoted

** Attach the list of SHGs to be promoted

11. Financial position of the organization as per Balance Sheet (As on _____)

a) Fixed Assets Rs. _____

b) Current Assets Rs. _____

c) Borrowing (Details of Borrowing, if any , may be given in the proforma below)

d) Other Liabilities Rs. _____

e) Excess of Expenditure over income or deficit, if any, please give detailed reasons, proposed step/sources to meet & latest position with explanatory note. (Amount in Rs.)

Sr. No.	Name of the Lending Institution	Date	Amount borrowed	Amount repaid	Balance of Borrowings Outstandings
1	2	3	4	5	6

12. Proposed programme for which amount of Interest Free Loan required by NGO from NMDFC (Amount in Rs.)

Sr. No.	Year	No. of SHGs to be formed & established (with other parameters given under para 10 of the application)	Amount Required (Rs.)	(Please give your estimate as per norm given in the scheme)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13. Check List: (Please enclose the following)

Sr. No.	Details of enclosures	Yes/No	Page
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Attested Copy of the original Registration Certificate/ Renewals, if any.		
2	Attested copy original Memorandum of Association/Bye-laws with latest amendments		
3	Indicate the provision to borrow from outside agency (pl. give Para/Page No. bye laws)	Page No. Para No.	
4	Main objectives/purpose/ background of forming the organisation - a brief note.		
5	Bio-data of the chief functionary.		
6	Composition of the current Managing Committee with name, designation and address of the members (with relevant copy of resolution of general body.)		
7	Photographs and signatures of the member of the current Managing Committee duly attested.		
8	Copy of the audited accounts and Balance Sheet of the organisation for the last three years along-with Auditors Report		
9	Copy of the resolution passed by Management Committee seeking loan (amount Rs .....) from NMDFC.		
10	Copies of Annual Report of last three years.		
11	Copies of testimonials received from funding agencies/Govt. Departments etc., if any.		

DECLARATION

I _____

(Full name with designation) certify that the facts and figures furnished in the application form and the annexure are correct and tally with the records of our organisation.

Place:

Date:

(Signature with official stamp)

Name & Designation of Chief Executive

Ends: _____ sheets.

****

Chapter 5

Addresses

Following are the addresses of National Commission for Minorities, States Minorities Commission and Names & Addresses of the State Channelising Agencies Of NMDFC for your ready reference.

Chapter 5a

Address Of National Commission For Minorities

Office Address:
National Commission for Minorities, 5th Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110 003 Tel. 24615583 Fax 24693302, 24642645, 24698410 Toll Free Number: 1800110088 E-mail: ro-ncm@nic.in

Chapter 5b
Addresses Of States Minorities Commission

No	Name	Address	Telephone/Fax No./Email
1.	**Andhra Pradesh**	No Commission	Fax-23452114
2.	Assam State Minorities Commission 1. Sh. Abdul Muhib Mazumdar, Chairman 2. Sh. Allen Brooks, Member 3. Dr MuktiDeb Choudhury, Member 4. Sh. Parvez Shah, ACS,Secy. cum AO	Assam State Minorities Commission RGB Road, New Ganeshgudi, Dispur, Guwahati - 781 006.	Ph. 0361-2383000 Mobile -9435345015
3.	Bihar State Minorities Commission 1. Sh. Naushad Ahmed, Chairman 2. Sh. Prahlad Kumar Sarkar, Member 3. Sh. Zaheer Malmali, Member 4. Sh. Razia Kamil Ansari, Member 5. Sh. Liyaqat Ali Mansoori, Member 6. Dr. Islam Rahi, Member 7. Sh. Shamshad Alam, Member	Bihar State Minorities Commission Barrack No. 7, Old Secretariat, Patna - 300 015	Mobile-9431476236 Ph-2213595 Fax-2215051

	8. Mohd. Abdullah, Member 9. Sh. T.B.S. Jain, Member 10. Mohd. Farooquzzamam, Section Officer		
4.	Chhattisgarh Minorities Commission Sardar Dalip Singh Hora,Chairman Sh. Murtja Vanak, Member Sh. M. R. Khan, Secy	Chhattisgarh Minorities Commission C-186, Shailendra Nagar, Raipur (C.G.) - 492 001	Ph-2434809 Fax-2445073
5.	Delhi State Minorities Commission, Pushpinder Singh, Member A.C. Michael, Member	Delhi State Minorities Commission, 1st Floor, C-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002	Tele/Fax-23370823-25 Email: dmc_nct@rediffmail.com
6.	Jharkhand Minorities Commission Dr. Shahid Akhtar, Chairman Bhushan Tiarky, VC Yaqoob Ansari, VC Shri Shailendra Singh, Member Md. Eqrarul Hasan, Member Sh. Rafique Anwar, Member Sh. Kari Barkat Ali, Memer Sh. Asgar Misbahi,	Jharkhand Minorities Commission Building No. 3, Artisen Hostel, Secrtor-3, Dhurwa Ranchi-834004	Ph-0651-2400946 Mobile-09534212588 Fax-06512400946 Email-chairman@jsmc.in

	Member Shi Samuel Guria, Member Sri Kalyan Bhattacharya, Member		
7.	Karnataka State Minorities Commission 1. Sh. Anwar Manippady, Chairman, 2. Sh. Ateeque Ahmed, Secretary,	Karnataka State Minorities Commission 5th Floor, Vesveshwariah Tower(M)Dr. B.R. Ambedkar Veedhi, Bangalore - 560 001.	Phone- 080 - 2286 4204 / 3400 Fax- 080-2286 3282 Email: secretary@karmin.in
8.	M.P. State Minorities Commission Sh. Trilochan Singh , Member Sh. Surjit singh Gill, PS to Member	M.P. State Minorities Commission, E-Block, Old Secretariat, Bhopal - 462 011	Ph-0755-2730873 Fax-0755-2733065
9.	Maharashtra State Minorities Commission 1. Sh. Munaf	Maharashtra State Minorities Commission Behind J.J. School of Arts, Mumbai	22650085 / 22610156

Chapter 5c

Names & Addresses of the State Channelising Agencies Of NMDFC

Andhra Pradesh	Assam
Andhra Pradesh State Minorities Financial Corporation 5th Floor, Haj House, Nampally, HYDERABAD-500 001 (A.P.) Ph. 040-23244500, 23244501 23244368 (Fax)	Assam Minorities Development & Finance Corporation R.G.B. Road, Dispur, GUWAHATI - 6 Ph. 036 1-2595480, 2207373
Bihar	**Chandigarh**
Bihar State Minorities Financial Corporation Ltd. Haj Bhawan, 1st Floor, 34 Harding Road, Ali Imam Path, PATNA - 800 001 Ph. 0612-224975, 2224975, 2215994 (Fax) www.bsmfcl.org	Chandigarh Scheduled Caste, Backward Classes & Minorities Financial & Development Corporation Ltd. Additional Town Hall Building, 3rd Floor, Sector 17-C, CHANDIGARH. Ph. 0172-2701449, 2707527, 2712797, 2708690 (Fax)
Chattisgarh	**Delhi**
Chhatisgarh State Antyavasayee Coop. Finance and Dev. Corpn. Ltd. B-9, Sector-5, Devender Nagar, Raipur, CHHATISGARH Ph. 0771- 4248601-15, 4248617 (Fax)	Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Dev. Corporation Ltd. Ambedkar Bhawan, Sector - 16, Rohini, DELHI - 110 054 Ph. 011-27570627, 27570502, 27572706, 27572630 (Fax)
Gujarat	**Haryana**
Gujarat Minorities Finance and Development Corporation 2nd Floor Block No.11, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, GANDHINAGAR - 382 010	Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam, SCO 813-14, Sector 22-A, CHANDIGARH - 160 022.

Ph. 079-23253757, 23254581, 23254583, 23254584, 23254152 (Fax)	Ph. 0172-2701722, 2701074, 2707539, 2726826 (Fax) Mewat Development Agency Housing Board Colony, Nuh, (Distt. Mewat) - 122 107. Ph. 01267-271179, 274603, 271461(Telefax)
Himachal Pradesh	Jharkhand
H.P. Minorities Finance and Development Corporation SDA Complex, Block No.3 8, First Floor, Kasumpti, SHIMLA - 171 009. Ph. 0177-2621669, 2621271, 2622164 (Telefax)	Jharkhand State Scheduled Tribes Cooperative Development Corporation Ltd. Balihar Road, Morabadi, RANCHI - 834 008 ,JHARKHAND Ph. 0651-2552398 (Off), 2551686 (Fax)
Jammu & Kashmir	
1st May to 30th October J&K Women's Development Corporation Old Secretariat, Block-A, 1st Floor, SRINAGAR Ph. 0194- 2450432	1st November to 30th April J&K Women's Development Corporation, Hall No.6-B, 2nd Floor, Aquaf Complex, Gandhi Nagar, JAMMU (J&K) Ph.0191-2430321,2439370
J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Sempora, Pampore, Pantha Chowk, SRINAGAR- 191101. Ph. 01933-224362/65/67, 224402 (Fax)	J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udhyog Bhawan, Railhead Complex, JAMMU - 180 012 Ph. 0191-24745 12, 2477327, 2477329 (Fax)
J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Government Industrial Estate LEH	J&K SCs/STs & BCs Development Corporation Romesh Market, Shastri Nagar,JAMMU - 180 004 0191-2433229, 2451762, 2452009

Kerala	
Kerala State Backward Classes Development Corporation "SENTINEL"2nd Floor, TC No.27/588 (7) & (8) Pattoor, THIRUVANTHAPURAM - 695 035. Ph. 0471-2577550, 2577539(Fax) www.ksbcdc.com	Kerala State Women's Development Corpn. T.C.20/2170, Opp. Manmohan Bunglow, Kowdiar P.O., THIRUVANTHAPURAM - 695 003. Ph. 0471-2727668, 2316006 (Fax), www.kswdc.org
Kerala State Cooperative Federation for Fisheries Development Ltd. Kamaleswaran, Manacaud P.O., THIRUVANTHAPURAM - 695 009. Ph. 0471- 2457172, 2457756, 2458606, 2457752 (Fax) www.matsyafed.org	
Karnataka	**Maharashtra**
Minorities Development Corporation Ltd. 12th Floor, Main Tower, Dr. B.R. Ambedkar Veedi, BANGALORE - 560 001 Ph. 080- 22861226, 22864720, 22860999, 22864782 (Fax) www.kmdc.in	Maulana Azad Alpsankhyak Aarthik Vikas Nigam DDA Building, 2nd Floor, Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Marg, MUMBAI - 400 023 Ph. 022-22633351, 22653080, 22672293, 22672294 (Fax)
Mizoram	
Mizoram Cooperative Apex Bank Ltd. Bazar Bungkawn, PB-138, AIZWAL - 796 001 MIZORAM Ph. 0389- 2312307, 2322744, 2317190, 2327765, 2327764 (Fax)	Zoram Industrial Development Corporation New Secretariat Complex, Khatla, Aizawl, P. Box - 125, AIZWAL - 796 001. MIZORAM Ph. 0389-2310190, 2326271(Fax)

Madhya Pradesh	
M.P. Backward Classes & Minorities Finance and Development Corporation Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, 1st Floor, 35, Shyamala Hills, BHOPAL - 462 002, Madhya Pradesh. Ph. 0755-2660209, 2660207-08, 2660390, 2660175 (Fax)	Madhya Pradesh Hastshilp Avam Hathkargha Vikas Nigam Ltd. Hastshilp Bhawan, 03 Hamidia Road, BHOPAL - 462 001. Ph. 0755-2676920, 2676927, 2676928, 2676926 (Fax)
Manipur	**Nagaland**
Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society Babupara, IMPHAL - 795 001, Manipur. Ph. 0385-2442539, 2451902	Nagaland Industrial Development Corpn. Ltd. IDC House, P.B. No.5, DIMAPUR - 797 112,NAGALAND. Ph. 03862-230571-74, 226473 (Fax) Nagaland Handloom & Handicrafts Development Corporation Ltd., P.B.No.81, Half Nagarajan, DIMAPUR - 797 112,NAGALAND Ph. 03862-224591, 230130, 230046 Nagaland State Social Welfare Board New Secretariat Complex, KOHIMA - 797 001, NAGALAND. Ph. 0370-22703 10, 2270307 (Fax)
Orissa	**Punjab**
Orissa Backward Classes Finance Development Cooperative Corporation Ltd. Q.No. A/6, Unit - 5, Near Rajiv Bhawan, BHUBANES WAR - 751 001. Ph. 0674- 2391061	Punjab State Backward Classes Land Development & Finance Corporation SCO No.60-61, Sector 17-A, CHANDIGARH 160 017. Ph. 0172-2709261, 2705982, 2705995

Pudducherry	Rajasthan
Puducherry Backward Classes & Minorities Development Corn. Ltd. No.5, Zamindar Gardens, PUDDUCHERRY - 605 001. Ph. 0413- 2332076, 2225859 (Telefax)	Rajasthan Minorities Finance and Development Corporation Ltd. Ambedkar Bhawan, Plot No.G-3/1, Room No.403/412, 3rd Floor, Near Civil Line Railway Crossing, JAIPUR(Rajasthan) Ph. 0141-2220258, 2220721 (Telefax)
Tamilnadu	**Tripura**
Tamil Nadu Minorities Economic Development Corporation 807, Anna Salai, Vth Floor, CHENNAI - 600 002. Ph. 044-285 14846, 28515450 (Fax)	Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Ltd. Lake Chowmuhani, Agartala, WEST TRIPURA - 799 005. Ph.0381-2326512, 2300083, 2328232 (Fax)
Uttar Pradesh	**Uttranchal**
U.P. Minorities Financial Development Corpn. Ltd. 746, 7th Floor, Jawahar Bhawan, Ashok Marg, LUCKNOW - 226 001. Ph. 0522-2236976, 2286401, 2286854, 2286053(Fax)	Uttranchal Alpsankhyak Kalyan Tatha Wakf Vikas Nigam 161, Old Nehru Colony, DEHRADUN (UTTRANCHAL). Ph. 0135- 2657747, 2652458, 2652458, 2665228 (Fax) www.alpsankhyak.org.in
West Bengal	
West Bengal Minorities Development and Finance Corporation "AMBER", DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, KOLKATA - 700 064. Ph. 033-23219619, 23212998 www.wbmdfc.org	

Chapter 6

The Gazette of India For Jain Minority

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

590 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Chapter 6

The Gazette of India For Jain Minority

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F.No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

380 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Chapter 7

भारतीय जैन संघठन (BJS) - एक परीचय

भारतीय जैन संघठन (BJS) यह समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सामाजिक संस्था है। जिसकी स्थापना इसके संस्थापक पूना निवासी श्री. शांतिलालजी मुथ्था ने १९८५ में की। यह संस्था सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक विकास तथा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य कर रही है।

BJS मुख्य रूप से राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना लक्ष केन्द्रित कर उनके निवारण हेतु गहराईसे अध्ययन कर समाधान प्रस्तुत करने का कार्य तीन दशक से कर रहा है।

BJS में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लगाकर शहर/गांव कार्यकारिणी की शृंखला स्थापित है। संस्था में पदाधिकारीयों का चयन चुनाव पध्दति से ना होकर मनोनयन पध्दति से होता है। पदाधिकारियों को मनोनित करने का संम्पूर्ण अधिकार संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। यह कार्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की सलाह से किया जाता है।

वर्तमान में BJS का कार्यक्षेत्र देश के लगभग २० राज्यों में है। संस्था में हजारो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता समर्पण भाव से समाज उत्थान के कार्य में लगे हुये है। पूना मुख्य कार्यालय में लगभग ५०० प्रोफेशनल लोग रिसर्च के माध्यम से समाज उपयोगी समाधान के मॉडल्स एवं कार्यक्रम तैयार करने का कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक कर रहे है। सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक विकास व आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पिछले तीन दशक में किये गये विशेष कार्य की जानकारी निम्नलिखित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि, BJS के कार्यों से जुडकर देश निर्माण में अपना योगदान दे।

सामाजिक उत्थान

समय काफी तेजीसे बदल रहा है। २५-३० वर्षों में बदलाव की जो रफतार रही है, वह पिछले १००-२०० वर्षों में भी अनुभव करने को नहीं मिली। तेजीसे बदलते हुए इस युग में 'परिवार' यह अवधारणा बिखर रही है, तथा इसे बांधे रखने का कार्य अत्याधिक कठीन होता जा रहा है। परिवार ही नहीं बचेंगे, तो समाज का अस्तित्व कैसे रहेगा? इस गंभीर समस्यापर BJS ने, परिवार में रहनेवाले प्रत्येक सदस्य की जरूरतों को समझकर, गहराईसे अध्ययन कर निम्नलिखित समाधान प्रस्तूत किये है।

छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम' कक्षा ४थी एवं ८वी के विद्यार्थीयों के लिए (Student Assessment Program - SAP 4th & 8th)

तीन घंटे की इस जांच परिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी बडे मजे से, खेल खेल में इस जांच परिक्षा में सहभाग लेते है, तथा बडी सहजता से पालकों को अपने बच्चों की भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक योग्यता व सामान्यज्ञान, स्वास्थ्य, संबधित विषयों पर जानकारी प्राप्त होती है। बीजेएस द्वारा, इस कार्यक्रम के माध्यम से, विद्यार्थीयों की क्षमता एवं योग्यता का आकलन कर, उन्हें अपनी रूचि अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राविण्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से, पालकों का विशेष मार्गदर्शन किया जाता है। SAP 4 अब Online www.bjssap.org पर भी उपलब्ध है।

कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम (Carrier Guidance Program)

स्पर्धा के इस युग में, दसवी तथा बारहवी के पश्चात विद्यार्थीयों ने कौन से शैक्षणिक क्षेत्र का चयन करना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र भविष्य की शिक्षा के लिए उपलब्ध है, कौन से कॉलेजों का चयन करना चाहिए, उनमें प्रवेश प्राप्त करने की क्या प्रणाली है, पिछले वर्ष का कट ऑफ प्रतिशत क्या था, इत्यादि अनेक प्रश्नों का सामना करना पडता है। इस विषय में, जानकारी के अभाव की वजह से, ना ही माता-पिता मदद कर पाते है और ना ही स्कूल मदद कर पाता है। आज के दौर में विद्यार्थीयों को योग्य कैरियर मार्गदर्शन की अत्याधिक आवश्यकता है। BJS अपने एक्सपर्ट कैरियर मार्गदर्शकों के माध्यम से परिवार की इस जरूरत की पूर्ती हेतू विद्यार्थी एवं पालकों के लिए कैरियर मार्गदर्शन के वर्कशॉप आयोजित करता है।

युवतियों का सक्षमीकरण' - २१ वी सदी की सामाजिक चुनौतियो का सामना करने हेतु Empowerment of Girls to face the social challenges of 21st century (EoG)

आज के इस दौर में, स्कूली शिक्षा पूर्ण कर, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज में प्रवेश करनेवाली, सोलह से पच्चीस वर्ष की युवतियों के समक्ष अनेक कठिनाईयाँ, आग के समान विक्राल रूप धारण किये खडी है। जैसे की

अपनेही परिवार में कैसे जीना, माता-पिता से संवाद कैसे करना, नए एवं अच्छे मित्रों का चयन कैसे करना, अपने आत्मविश्वास को टिकाये कैसे रखना, मिडीया-मोबाईल-इंटरनेट के दुष्परिणाम से कैसे बचना, व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना, पारंपरिक विवाह व प्रेम विवाह के गुण एवं दोष का पूर्व आकलन कैसे करना, इत्यादि अनेक प्रकार की आग आज जमाने में लगी है। इस आग को हम बुझा सकते नहीं। लेकिन इसका सामना करने के लिए युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से फायर फायटर जरूर बना सकते है। यह अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। BJS ने अपने तीन दशक के सामाजिक अनुभव के आधार पर, युवतियों को सक्षम करने हेतु, एक्सपर्ट के माध्यम से तीन दिवसीय कार्यशाला तैयार की है। यह कार्यशाला युवतियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर, इस सदी की सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाती है। इस कार्यक्रम के द्वारा ११ राज्यो में १०,००० से अधिक युवतियों का सक्षमीकरण किया गया है। EoG अब Online (www.eogonline.org) पर भी उपलब्ध है।

युवक-युवती परिचय संमेलन (Matrimonial Meet)

योग्य जीवन साथी की तलाश सभी परिवारों को है। परिवार कितनाही समृध्द क्यों न हो, शिक्षित क्यों न हो, नामी क्यों न हो, योग्य रिश्तों की कमी सभी को है। ढूँढने पर भी योग्य रिश्ते मिल नहीं पाते। नजदीक के रिश्तेदार भी, ना ही रिश्तों की जानकारी देते है और ना ही रिश्तों के बीच में पडते है। रिश्ते ठीक से मिलेंगे नहीं तो जुडेंगे कैसे? रिश्ते ठीक से जुडेंगे नहीं तो टिकेंगे कैसे? रिश्ते ठीक से टिकेंगे नहीं तो परिवार आगे बढेंगे कैसे? BJS ने सन १९८५ में इस समस्या को समझा, गहराईसे अध्ययन किया तथा 'परिचय संमेलन' विकल्प के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तूत किया। एक ही दिन में, एक ही स्थान पर, अपने बेटे या बेटी के लिए, पचास-सौं रिश्तें उपलब्ध करवाने का मंच है, 'परिचय संमेलन'। समाज की जरूरतों को समझते हुए विभिन्न प्रकार के परिचय संमेलन आयोजित किये जाते है। जैसे की, प्रोफेशलन परिचय संमेलन, उच्च शिक्षित परिचय संमेलन, सामान्य शिक्षित परिचय संमेलन, शहरी परिचय संमेलन, ग्रामीण परिचय संमेलन, पुर्नविवाह हेतु परिचय संमेलन। पिछले तीन दशक में इन परिचय संमेलनों को अत्याधिक प्रतिसाद मिला है। तथा रिश्ते तय करने में परिचय संमेलन वरदान साबित हुए है।

आगामी परिचय संमेलन किन शहरों में आयोजित किये जा रहे है, इसकी जानकारी www.bjsindia.org वेबासाईट पर उपलब्ध रहती है।

नव विवाहितों का सक्षमीकरण - सुखी घर परिवार के लिए Empowerment of Couples for Happy Family & Happy Home (EoC)

आज के जमाने में रिश्तें तय होने जितने कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है, रिश्ते निभाना। छोटी छोटी बातों पर बडी बडी खटपट होने लगी है। खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, पहनावा आदि में अत्याधिक बदलाव आये है। जीने के तौर तरिके बदल गए है। पति - पत्नी दोनों ही शिक्षित, उच्चशिक्षित है। करियर ने घरेलू कामकाज के ऊपर प्राथमिकता ले ली है। धैर्य, समर्पण, विश्वास, सामंजस्य, सुसंवाद आदि में काफी कमी आयी है, वहीं अहंकार अत्याधिक बढ गया है। यही सब वजह है, रिश्तों मे दरार की व परिवारो मे बिखराव की। भारतीय जैन संघठन के संस्थापक, दूरदृष्टा श्री. शांतीलालजी मुथ्था ने सन २०१० मे जैन समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की, कि आनेवाले दस-पंद्रह वर्षों में हर दो विवाह में से एक विवाह टुटेंगा। अगर सही में ऐसा होता है, तो यह समाज के अस्तित्व के लिए अत्याधिक हानिकारक होगा। इस बात को ध्यान में रखकर BJS ने नवविवाहीतों (विवाह के दस वर्ष तक) में आपसी सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित रहने के दृष्टिकोन से दो दिवसीय कार्यशाला तैयार की है। इस दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से नव विवाहित जोडो तथा उनके पालको के आपसी सम्बधो मे सामंजस्य, बेहतर संवाद, संगठित एंव संयुक्त रहने की भावना, एक दूसरे का विशेष ध्यान, देखभाल, त्याग एंव समर्पण भाव के साथ वैवाहिक और परिवारिक दायित्व एंव सम्बधो को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यवसाय वृद्धि कार्यक्रम (Business Development Program)

परिवर्तन के इस युग में पारंपारिक व्यवसायों मे नई पिढी की घटती रूची, पुराने व्यवसायों के अस्तित्व का प्रश्न, मॉल संस्कृती का प्रभाव, व्यवसाय की नई संभावना के प्रति दुर्लक्ष, नई पिढी के कार्यक्षमता का पूरा उपयोग ना होना आदि बातों की वजह से व्यवसाय मे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। BJS अपने एक्सपर्ट प्रोफेशनल मार्गदर्शकों के माध्यम से नये एवं पुराने व्यवसायियों के लिए Business & Entrepreneurship Development Program द्वारा मार्गदर्शन करता है।

प्लॅस्टिक सर्जरी (Plastic Surgery)

BJS सन १९९० से लगातार, छोटे बच्चों के कटे फटे ओंठ, (Cleft leaf) पलक एवं नाक और कान की बाह्य विकृती, चेहरे के दाग आदि का उपचार निशुल्क प्लॅस्टिक सर्जरी के द्वारा, अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के माध्यम से कर रहा है। अब तक दो लाख पचास हजार से ज्यादा निशुल्क प्लॅस्टिक सर्जरी BJS द्वारा की गई है।

अल्पसंख्यक सम्बंधित जानकारी (Minority Cell)

२७ जनवरी २०१४ को भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। अब तक मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, सिख एवं पारसी धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की अनेक योजनाओं के लिए प्रति वर्ष करोडों रूपये का प्रावधान बजट में किया जाता है। जैन समाज के विद्यार्थियों कि शिक्षा एवं छात्रवृत्ति कि विविध योजनाए, शैक्षणिक संस्थाओ कि स्थापना एवं प्रशासन की विविध योजनाएँ, युवतियाँ एवं महिलाओं के सक्षमीकरण की योजनाएँ, व्यवसाय के विकास की विभिन्न योजनाए, धर्मस्थान की सुरक्षा की विभिन्न योजनाए एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज उत्थान की विविध योजनाए उपलब्ध है।

BJS द्वारा संकलनीत, निम्नलिखित पुस्तकों के माध्यम से अल्पसंख्यक योजनाओं व लाभ की जानकारी जैन समाज के सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

१) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन विद्यार्थियों को लाभ
२) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं को लाभ
३) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की धार्मिक संस्थाओं को लाभ
४) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन महिलाओं को लाभ
५) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन व्यवसायीयों को लाभ
६) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन सामाजिक संस्थाओं को लाभ

यह पुस्तके भारतीय जैन संघठन के मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते है अथवा www.bjsindia.org वेबसाइट से डाऊनलोड भी कर सकते है।

शैक्षणिक विकास

सामाजिक उत्थान के कार्य के साथ साथ, देश निर्माण का कार्य भी भारतीय जैन संघठन की प्राथमिकता रही है। देश निर्माण के कार्य में शैक्षणिक विकास की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः भारतीय जैन संघठन ने इस विषय पर भी अपना लक्ष केंद्रित किया है।

देश में जैन समाज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा २५०० शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण १००-१५० वर्ष पूर्व किया गया। इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, सभी जाती धर्म के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा, सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। भारतीय जैन संघठन द्वारा सन २००२ में फेडरेशन ऑफ जैन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट (FJEI) की स्थापना की। जैन समाज की १७०० शैक्षणिक संस्थाएँ इस फेडरेशन का हिस्सा है। सभी संस्थाओं का अपना अस्तित्व कायम रखते हुए, इन संस्थाओं द्वारा मूल्यआधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थियों तक पहूँचाना ही भारतीय जैन संघठन की प्राथमिकता है। साथ ही साथ, यह मूल्यआधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, देश की १३,००,००० सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलों में भी लागू करने का ध्येय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए BJS ने निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार कर देश के लिए उपलब्ध किये है।

स्कूल ॲसेसमेंट ॲन्ड ॲक्रेडिटेशन (School Assessment & Accreditation)

देश में कॉलेजों की गुणवत्ता का विकास करने की दृष्टिकोन से सरकार ने १९९४ में National Assessment & Accrediation Council (NAAC) का गठन किया। लेकिन ऐसी कोई योजना स्कूलों के लिए उपलब्ध नहीं है। इगड ने सन २००४ में स्कूलों के ॲसेसमेंट और ॲक्रेडिटेशन का कार्यक्रम तैयार कर देश की चार हजार से अधिक सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलो में क्रियान्वित किया। यह कार्यक्रम उपचारात्मक पध्दति का कार्यक्रम है। निर्धारित संकेतको व मानको के आधार पर स्कूल की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। सुधार के आवश्यक क्षेत्रों का पता लगाता है। स्कूल के मुख्याध्यापक एवं प्रबंध समिति को विशेष सुधार की क्रियाओं से अवगत कराता है। जिससे स्कूल की प्रक्रिया मे गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय जैन संघठन ने यह स्कूल ॲसेसमेंट ॲन्ड ॲक्रेडिटेशन कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध किये है। जिसके माध्यम से उन राज्यों की सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलों में गुणवत्ता विकास होने में सुविधा

मिलेगी। भावी पिढी को मुल्यआधारित गुणवत्तायुक्त शिक्षण द्वारा तैयार कर सशक्त देश निर्माण के स्वप्न को पूर्ण करने का लक्ष है।

मूल्यवर्धन (Value Education Program)

संस्कृती प्रधान इस देश में मूल्यों का पतन हो रहा है। आपसी भाईचारा, एक दुसरे के प्रति सौहार्द, सहिष्णुता, प्रामाणिकता आदि गुण कम होते जा रहे है। तथा इनकी जगह दुर्व्यसन, संवेदनहिनता, हिंसा आदि ने स्थान ले लिया है। भावी पिढी को गुणवत्ता आधारित शिक्षण के साथ साथ मूल्यआधारित शिक्षण भी देना आज की प्राथमिकता हो गई है। भारतीय जैन संघठन ने इस बात को ध्यान में रखकर सन २००९ में 'मूल्यवर्धन' नामक पाठ्यक्रम तैयार कर महाराष्ट्र के बीड जिले में सरकार की सहमती से ५०० स्कूल के ३५,००० बच्चों पर प्रयोगात्मक कार्य शुरु किया है। मूल्यवर्धन कार्यक्रम का विद्यार्थियों पर, उनके परिवारों पर, आसपास के क्षेत्र पर क्या परिणाम हो रहा है, यह जानने के लिए NCERT, Cambridge University (UK), Oregon University (USA) जैसी राष्ट्रीय एवं आतंरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा Impact Assessment कराया गया, तथा इसके परिणाम उत्साहवर्धक है। विद्यार्थी केंद्रित यह पाठ्यक्रम देश की सभी स्कूलों के लिए आज उपलब्ध है। शैक्षणिक क्रांति करने की क्षमता जैन समाज में है। १३,००,००० स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी देश का भविष्य है। इन्हीं स्कूलो के माध्यम से गुणवत्तायुक्त मूल्य आधारित शिक्षण इन विद्यार्थियों तक पहूँचाना ही भारतीय जैन संघठन का उद्देश है। सन २००५ में विश्व की सभी सामाजिक संस्थाओं के संघठन (World Association of Non Governmental Organization - WANGO) ने भारतीय जैन संघठन को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च स्वयंसेवी संस्था के रूप में सम्मानित किया।

आदिवासी समाज विकास कार्यक्रम (Tribal Project)

BJS द्वारा सन १९९७ से महाराष्ट्र के मेलघाट एवं ठाणे से हर वर्ष आदिवासी समाज के ५० बच्चों को निशुल्क शिक्षा हेतु पुना के इगड स्कूल में प्रवेश देते है। इन विद्यार्थीओं को ५ वी कक्षा से १२ वी कक्षा तक पढाई, लिखाई, उनको लगने वाले पुस्तके व साहित्य, कपडे लत्ते, खाना-पिना तथा होस्टेल में रहने कि निशुल्क सुविधा इगड द्वारा की जाती है। स्कूल की पढाई के अलावा इन विद्यार्थीयों को व्यक्तीत्व विकास, जरूरत मंद विद्यार्थीयों को ट्यूशन्स आदि दिया जाता है। बारहवी कक्षा के पश्चात इन विद्यार्थीयों को प्रोफेशनल कोर्स में ॲडमिशन हो सके इस बात को ध्यान में रखकर इन आदिवासी विद्याथीयों को तैयार किया जाता है। उद्देश यह है, की प्रोफेशनल

बनने के बाद यह बच्चे अपने समाज की मदद कर आदिवासी समाज को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य करेंगे। पिछले २ दशक में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिले है।

आपदा प्रबंधन

जैन समाज संवेदनशील समाज है। जब भी देश में कोई नैसर्गिक आपदा आती है, तो जरूरतमंद देशवासियों को मदद करना यह जैन समाज की प्राथमिकता रही है। पिछले दो दशक से भारतीय जैन संघठन ने देश में आये हुए सभी प्रमुख नैसर्गिक आपदा में निम्नलिखित रूप से अपना योगदान दिया है।

- **१९९३ लातूर भूकम्प:** १२०० बच्चो का कक्षा ५वी से स्नातक स्तर तक शैक्षणिक पूर्नवसन
- **१९९७ मेलघाट कुपोषण:** ३५० बच्चों का १० वर्षों तक निरंतर शैक्षणिक पूर्नवसन
- **१९९७ जबलपूर भूकम्प:** ५० छात्रों का शैक्षणिक पूर्नवसन
- **२००१ गुजरात भूकम्प:** मात्र ९० दिनों में ३६८ शालाओं का पुर्ननिर्माण कर प्रशासन को हस्तांतरण
- **२००२ अकोला बाढ:** १५,००० बाढ पीडितो के लिए अस्थाई आवास निर्माण करना
- **२००४ त्सुनामी:** अंदमान निकोबार द्वीप समूह में १ वर्ष में ११ स्कूलो एवं ३४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कर प्रशासन को हस्तांतरण
- **२००५ जम्मू और कश्मीर भूकम्प:** मात्र ४० दिनों में ८७० मकान का सामान उपलब्ध कर १५,००० पीडितो को आवास प्रदान करना
- **२००५-२००६ महाराष्ट्र बाढ:** ५००० बाढ पीडितों को घरेलू आवश्यक उपयोगी सामग्री का वितरण
- **२००८ बिहार बाढ:** १,५०,००० बाढ पीडितों को १८१ दिन निरंतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना

- **२०१३ महाराष्ट्र अकाल:** महाराष्ट्र के बीड जिले में ११५ सुखा प्रभावित तालाबों का सफाई कार्य (Desilting) मात्र १ माह मे किया, २० लाख लिटर पानी की क्षमता इन तालाबो में बढ गई। तथा Silt के माध्यम से पांच हजार एकड़ बंजर भूमी को उपजाऊ बनाने का कार्य किया।

  ७ सुखा प्रभावित जिलों में १०,००० पशुओं के लिए २८ पशू शिबिरों की स्थापना कर प्रबंधन का कार्य किया।

सन १९९३ से अबतक BJS ने आपदा प्रबंधन के कार्योकी सराहना महाराष्ट्र विधान सभा से लेकर भारत की लोकसभा में की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) व आयआयएम रायपुर ने ३ दिसंबर २०१३ को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उच्चतम काम करनेवाले ९ संस्थाओं को गौरवान्वित किया उसमें ८ सरकारी संस्थाएँ थी व BJS ही एकमात्र स्वयंसेवी संस्था को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

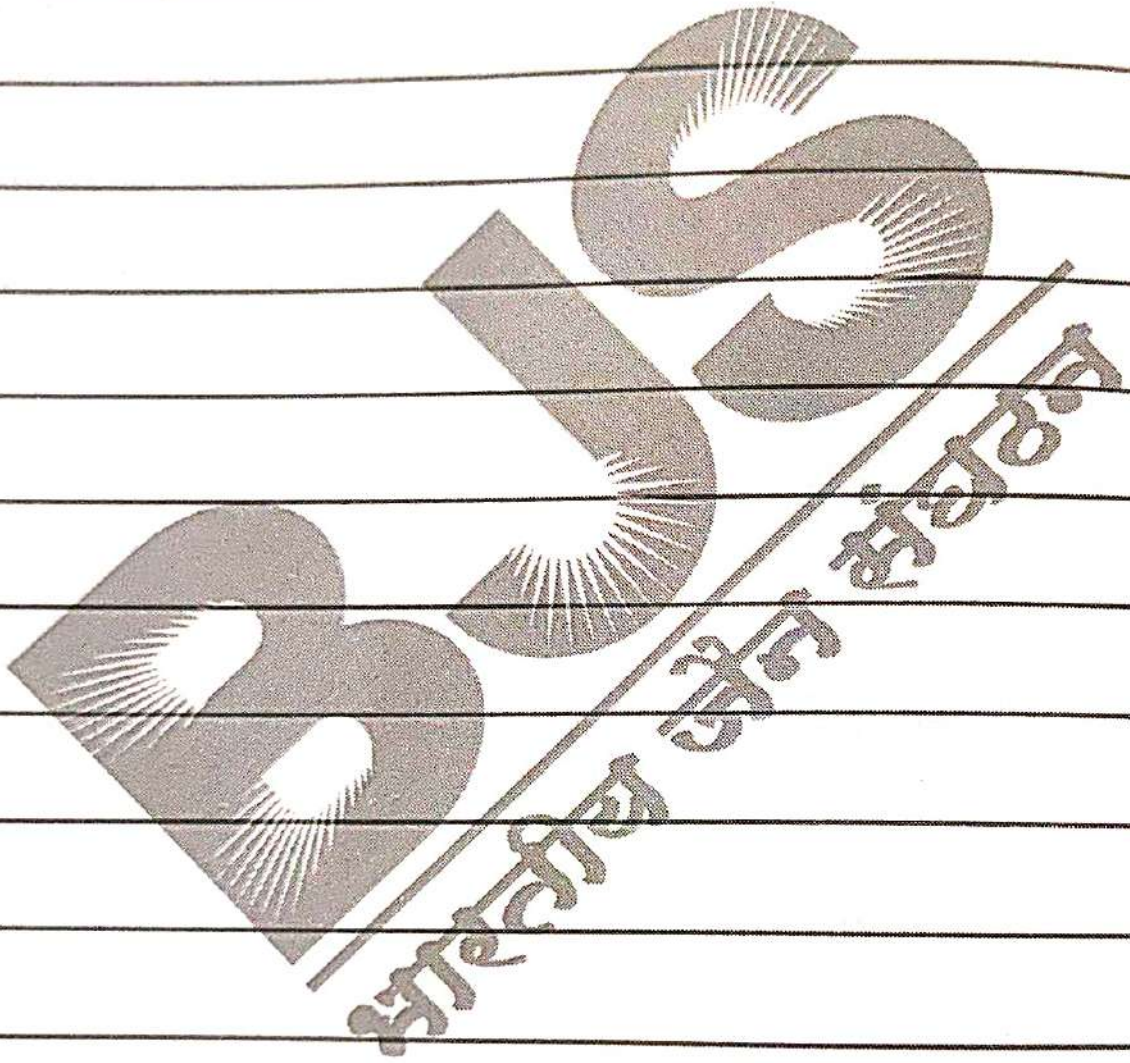

BJS Happenings

Leaders of Jain community meeting Law Minister Shri.Kapil Sibal for Jain Minority issue.

Girls giving introduction at a Matrimonial meet

Girls participating in Empowerment of Girls (EOG) programme

Dr. Parag Sancheti, Chairman of Sancheti Hospital, Pune addressing at inaugural programme of "Free Plastic Surgery Camp"

Dr. Raghunath Mashelkar, eminent scientist felicitating a member of recently formed BJS Ex-Student Alumni

Members participating in BJS National Executive Council meeting at Aamby Valley, Lonavla

BJS programmes and activities

Social Development

- Empowerment of Girls (EOG)
- Empowerment of Boys (EOB)
- Empowerment of Couples (EOC)
- Matrimonial Meet
- Plastic Surgery Camps
- Minority Cell
- Student Assessment Programme (SAP) Std. IV, VIII
- Career Guidance
- Mass Marriages
- Basic Family & Marriage Counseling Course (BFMC)
- And many more....

Educational Initiatives

School Assessment and Accreditation

- Process Assessment
  - Critical expert evaluation of school processes for internal improvement plans
  - Based on comprehensive key areas of school operations
- Profile Classification
  - Placement of School with respect to availability of infrastructure, facilities and human resources
  - Useful for fund-based development planning
- Grading of school
  - Third party validated report for school's outreach
  - Based on extensive feature list of school
- Member of CBSE Empanelment for School Quality Assessment and Accreditation

Mulyavardhan- a value education programme

Imbibe universal values and morals and build the character of a child from the formative years.

- Thorough Design
  - Extensive research on global trends in decline in values & its root causes
- Innovative Teaching-Learning Methods
  - Emphasis on self evaluation rather than examination for stress free learning
- Universal applicability
  - Universal context maintained along with the regional flavour
- Sustainable implementation
  - Covering total 38,000 students of 500 Primary schools of Patoda, Ashti tehesil of Beed & Municipal Corporation schools of Jalgaon, Maharashtra

Disaster Response

- **1993: Latur Earthquake, Maharashtra**
  Educational Rehabilitation of 1200 boys (Std V to graduation)
- **1997: Melghat Malnutrition Project**
  Educational Rehabilitation of 350 boys from tribal community for 10 years.
- **2001: Gujarat Earthquake**
  Re- constructed 368 schools in 90 days and handed over to the government.
- **2002: Akola floods**
  Temporary shelters provided to 15,000 victims.
- **2004: Tsunami**
  - Rescue and relief operations through 6 camps in Tamil Nadu.
  - Constructed 11 schools and 34 primary health centres in 1 year at Andaman & Nicobar islands.
- **2005: Jammu & Kashmir Earthquake**
  870 pre-fabricated shelters despatched for giving refuge to 15,000 affected people.
- **2008: Bihar floods**
  Medical aid to 1,50,000 victims in 181 days.
- **2013: Maharashtra Drought**
  - Desilting of 115 water bodies in drought-prone district of Beed within a period of one month as a long-term mitigation measure.
  - Establishment and management of 28 cattle camps in 7 drought ridden districts for 10,000 animals.

BJS
भारतीय जैन संघठन
Bharatiya Jain Sanghathan
Mutha Towers, Don Bosco Road, Near Golf Course, Yerawada, Pune - 411 006
Telefax: +91-20- 4120 0600
Email: info@bjsindia.org
Website: www.bjsindia.org
Facebook: www.facebook.com/BJSIndia